

पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार की ढाई लाख रुपए की 25 पेटी अवैध शराब जब्त

2

सामाजिक प्रतिक्रिया की युद्धपोष
बच्चों के पोषण में डिजिटलीकरण न बने बाधा

नवरात्रि में मास- मछली की दुकानें बंद रखने बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन

4

रानी दुर्गावती के मार्ग पर जनजातीय विकास का नया अध्याय

6

8

सार-समाचार

भारत-यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास 'माउंटेन गार्डियन' शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास 'माउंटेन गार्डियन 2026' सोमवार से शुरू हो गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास 18 अक्टूबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल, आपसी समझ और सहयोग बढ़ाना है। अभ्यास में पहाड़ी युद्ध पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अभ्यास में दोनों देशों के कुल 92 सैन्यकर्मों हिस्सा ले रहे हैं। दोनों सेनाओं की बराबर भागीदारी है। भारतीय दल में भैरव बटालियन के जवान और यूएई के दल में माउंटेन इन्फैंट्री बटालियन के जवान शामिल हैं।

फ्रांस में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद 500 विद्यालय बंद

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा के स्तर में गिरावट को लेकर जारी छात्र आंदोलन के हिंसक होने के बाद सोमवार को देश भर के करीब 500 विद्यालयों को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में दंगे को नियंत्रित करने वाली पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच हुई तीखी झड़पों के बाद सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री एडुआर्ड ग्रेफ्रे ने बताया कि सुरक्षा स्थितियाँ पूरी न होने के कारण लगभग 400 से 500 उच्च विद्यालयों में कक्षाओं को 'पूर्ण या आंशिक रूप से निर्लब्धित' कर दिया गया है।

पटना की सड़कों पर उतरे दारोगा परीक्षा अभ्यर्थी

पटना, एजेंसी। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को एक बार फिर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस बार दारोगा अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) द्वारा मुख्य परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के विरोध में सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा को रद्द करने के निर्णय को वापस लेने और घोषित परिणाम को मान्य करने की मांग कर रहे थे। दारोगा अभ्यर्थी बड़ी संख्या में जेपी गोलंबर के पास जुटे और प्रदर्शन शुरू किया।

राहुल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए

भोपाल, देशबन्धु। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर जारी गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कहा कि वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उन्हें भेजे गए नोटिस वापस लिए जाने चाहिए। राहुल ने अपने पत्र में कहा कि सीमित पदों के कारण बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के अवसर से वंचित हो रहे हैं। इनमें कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं, जबकि कई अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं भी दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि लंबे समय से इंतजार कर रहे कुछ अभ्यर्थी आयु सीमा के करीब पहुंच गए हैं। कांग्रेस नेता ने इस बात पर हैरानी जताई कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ये शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन और भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं, और तब भी इनकी बात सुनने के बजाय सरकार उन्हें नोटिस भेज कर डराने की कोशिश कर रही है। राहुल ने पत्र में लिखा कि इंदौर में छात्रों की गुंज कार्यक्रम के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों ने भर्ती में पदवृद्धि की मांग उठाई।

एसआईआर विवाद के बीच सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी टिप्पणी

फॉर्म-6 में बदलाव की हमने नहीं दी मंजूरी

फॉर्म 6 में बदलाव किसने किया है। कोर्ट अब निर्वाचन आयोग की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब और संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर आरोपों की जांच करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि आयोग के जवाब से यह सामने आता है कि ऐसे फैसले लिए गए थे, जिनके लिए आवश्यक सर्वसम्मति नहीं थी, तो कोर्ट उन फैसलों को वापस लेने या रद्द करने पर विचार कर सकता है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नोटिस के बाद, अगर वे आकर दिखाते हैं कि फैसले बिना सर्वसम्मति के लिए गए थे, तो हम उन फैसलों को वापस ले लेंगे।



दौरान वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 के किसी भी बदले हुए रूप को मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि जब रिकॉर्ड पेश किया जाएगा तो हम देखना चाहेंगे कि

ज्ञानेश ने फॉर्म में बदलाव कर भाजपा की मदद की

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में अवैध और एकतरफा बदलाव किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पद का दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। श्री गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा 'अब यह स्पष्ट हो गया है कि श्री ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में अवैध और एकतरफा बदलाव किया है और यह बदलाव स्पष्ट रूप से भाजपा की मदद के लिए किया गया। यह उनके पद के दुरुपयोग का एक और प्रमाण है। इस मामले की साजिश में शामिल सभी लोगों को 'वोट चोरी' के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।' उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म-6 में अवैध बदलाव की बात चुनाव आयोग के अपने आयुक्तों ने भी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि यह भी सामने आना चाहिए कि चुनाव आयोग में किसके आदेश पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) से यह बदलाव कराया।

ध्यान भटकाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने जनता को किया सचेत

■ अपनी मांगो से पीछे नहीं हटेगा विपक्ष

■ चौथे दिन भी जारी रहा विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली, देशबन्धु। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को पद से हटाने और एसआईआर रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष के सभी सांसद मंगलवार को संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करेंगे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि विपक्ष अपनी तीन मांगों से पीछे नहीं हटेगा। इसमें पहली यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा दें, दूसरी एसआईआर को रद्द किया जाए और तीसरी मांग



यह है कि चुनाव ईवीएम के बजाए बैलेट पेपर से कराए जाएं। इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन सड़कों पर। उन्होंने अन्य संगठनों व सिविल सोसायटी के संघर्ष को सांकेतिक तरीके से चेतावनी भी दी है कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है, जिसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस बीच चौथे दिन सोमवार को भी दिल्ली में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुए। एक तरफ कांग्रेस की

ज्ञानेश के खिलाफ विपक्षी सांसदों का मार्च आज

यह है कि चुनाव ईवीएम के बजाए बैलेट पेपर से कराए जाएं। इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन सड़कों पर। उन्होंने अन्य संगठनों व सिविल सोसायटी के संघर्ष को सांकेतिक तरीके से चेतावनी भी दी है कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है, जिसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस बीच चौथे दिन सोमवार को भी दिल्ली में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुए। एक तरफ कांग्रेस की

महिला पत्रकारों ने राहुल से मिलकर बताई पुलिस की बर्बरता

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में पुलिस पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार नफीसा और उनकी बहन ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। नफीसा ने कथित मारपीट में शामिल पुलिस अधिकारियों के नाम बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए थाने और संबंधित स्थानों के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए। नफीसा ने बताया कि मारपीट की घटना में एसएचओ दिनेश कुमार और एसआई सोनम समेत अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका रही। उन्होंने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग राहुल गांधी के सामने रखी। पत्रकारों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक होने से यह स्पष्ट हो

गंभीर संवैधानिक संकट में है बांग्लादेश

शेख हसीना बोली, जनता को तय करना है देश का भविष्य

जिनेवा, एजेंसी। बांग्लादेश का भविष्य डर या ताकत के जरिए नहीं, बल्कि वहां के लोगों की स्वतंत्र और पूरी जानकारी के आधार पर दी गई राय से तय होना चाहिए। देश इस समय 'गंभीर संवैधानिक संकट' से जूझ रहा है। यह बात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जिनेवा प्रेस क्लब में आयोजित एक सेमिनार में कही। हाल ही में जिनेवा में आयोजित इस सेमिनार का विषय था 'बांग्लादेश का संवैधानिक संकट: शिक्षा का अधिकार, मनमानी हिरासत और ट्रिब्यूनल के कथित तौर

www.deshbandhu.co.in

भोपाल | सागर | नर्मदापुरम | जबलपुर | सतना | रायपुर | बिलासपुर | नई दिल्ली



नर्मदापुरम, मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

संस्थापक-संपादक : स्‍व. माधाराम सुरजन

मताधिकार पर जस्टिस भुईयां की अहम टिप्पणी

ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए देश में तेज हो रहे आंदोलन, चुनाव चोरी के मसले पर मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ बढ़ते संदेह के बीच एक राहत देने वाला बयान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुईयां की तरफ से आया है। हालांकि जस्टिस भुईयां ने यह टिप्पणी किसी सुनवाई के दौरान नहीं की है, न ही यह किसी फैसले का हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश होने के नाते ही उनकी यह टिप्पणी काफी अहम है, क्योंकि इसमें नागरिकता और मताधिकार के बीच के अटूट संबंध को रेखांकित किया गया है। एसआईआर पर विवाद इसी वजह से भी उठे हैं कि मतदाता सूची शुद्धिकरण के नाम पर दस-बीस नहीं कम से कम 13 करोड़ लोगों से मताधिकार छीन लिया गया है। मताधिकार छीनने की कवायद को जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार के समान बताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रक्रिया लाखों भारतीय नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित कर उन्हें अपने ही देश में बिना वोट वाले नागरिकों में बदल देती है, तो ऐसी प्रक्रिया 'स्वाभाविक रूप से मनमानी' होगी और संविधान के मूल ढांचे पर चोट करेगी।

हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आयोजित 19वें जस्टिस बोध राज साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन पर जस्टिस भुईयां ने कहा कि भारतीय संविधान नागरिकों की दो श्रेणियां नहीं बनाता- एक वे जिनके पास वोट देने का अधिकार है और दूसरी वे जिनके पास यह अधिकार नहीं है। वोट छीनने वाली किसी भी प्रक्रिया को स्वभावतः मनमाना बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे किसी भी तरह की दलील या बहाने से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उनके मुताबिक ऐसी स्थिति संविधान के ‘दिल’ पर चोट करती है और भारत द्वारा अपनाए गए संवैधानिक शासन-व्यवस्था की ही नकार बन जाती है। जस्टिस भुईयां ने अपने भाषण में सीधे तौर पर न एसआईआर का नाम लिया, न ज्ञानेश कुमार का जिक्र इस संदर्भ में किया, न ही सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को जायज ठहराने वाले जो फैसले पिछले कुछ वक्त में आए हैं, उन पर कुछ खटा, लेकिन यह सब सीधे तौर पर न कहते हुए भी जस्टिस भुईयां ने अपने भाषण में दो टूक कहा कि किसी भारतीय नागरिक की पहचान से उसके वोट देने या मतदाता सूची में शामिल होने के अधिकार को अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसकी तुलना शरीर से आत्मा निकालने से की। यानी नागरिकता और मताधिकार को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कानून के विद्यार्थियों और भावी वकीलों के जरिए देश को याद दिलाया कि भारत जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक के लिए सरकार के संचालन में भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण और सीधा माध्यम उसका वोट है। उन्होंने कहा कि मताधिकार नागरिकता का सार है और यही वह माध्यम है जिसके जरिए देश का सामान्य नागरिक शासन-व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है।

जस्टिस भुईयां ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों को वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने की संवैधानिक व्यवस्था करता है। जस्टिस भुईयां ने साफ कहा कि अनुच्छेद 326 के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई प्राधिकरण ऐसा नहीं कर सकता और कोई अदालत भी ऐसी प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दे सकती जो संवैधानिक मताधिकार को बड़े पैमाने पर खत्म करती हो। उन्होंने कहा कि ‘कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है।’

इसके साथ ही जस्टिस भुईयां ने अनुच्छेद 326 को संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत से भी जोड़ा। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। जस्टिस भुईयां के अनुसार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इस समानता को वास्तविक लोकतांत्रिक अर्थ देता है। यानी समाज में ऊंची स्थिति वाला व्यक्ति और सबसे निचले सामाजिक-आर्थिक पायदान पर खड़ा व्यक्ति दोनों की नागरिक के तौर पर एक जैसी हैसियत है और दोनों के चुनाव में एक-एक वोट हैं। उन्होंने इसे शारीर संविधान के उस पर्यवेदनकारी दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के बावजूद राजनीतिक समानता सुनिश्चित की गई है। जस्टिस भुइयां ने अनुच्छेद 325 का भी उल्लेख किया। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य मतदाता सूची का प्रावधान है। जस्टिस भुईयां ने बाबा साहेब अंबेडकर के उद्देश्य को याद दिलाया कि संविधान निर्माताओं ने मताधिकार को केवल संसद द्वारा बनाए जाने वाले सामान्य कानून के भरोसे नहीं छोड़ा, बल्कि इसे संविधान में ही जगह दी।

इसके साथ ही जस्टिस भुईयां ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी मतदाता का नाम एक बार मतदाता सूची में दर्ज हो जाने के बाद, मृत मतदाता के मामले को छोड़कर, उसे बिना नोटिस और सुनवाई के हटाना नहीं जा सकता। यह टिप्पणी एसआईआर के संदर्भ में खास महत्व रखती है। एक अकादमिक कार्यक्रम में जस्टिस भुईयां के संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित भाषण का महत्व एसआईआर तत्काल बंद करने की मांग के बीच और बढ़ जाता है। नेन्द्रे मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के कारण देश में लोकतंत्र कुचलने का जो निराशाजनक माहौल बनाया गया है, उसमें इन दिनों चल रहा आंदोलन और इसके साथ जस्टिस भुईयां का भाषण वैसा ही है जैसा फेज़ अहमद फेज़ ने कहा था कि-बीमार को बेवक़्र करार आ जाए।

पितृसत्ता से लेकर जाति का विनाश, इतिहास के गैर-ब्राह्मणीकरण से मनु का श्राप तक” —पहली नजर में शैशव यह किसी को भी सामाजिक सुधार और जागरण की कार्यसूची लग सकती है। जाहिर है कि फुले दम्पति, पेरियार, डॉ अम्बेडकर तथा अन्य तमाम समाज सुधारकों की नहीं, अपने जरा अलग तरीके से गांधी की तथा उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की कार्यसूची का भी यह सब जरूरी हिस्सा रहा था। इसीलिए तो, इस राष्ट्रीय आंदोलन के गर्भ से जिस स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ, उसका संविधान कम से कम इस कार्यसूची के अनुरूप जरूर था। इससे स्वाभाविक अपेक्षा तो यही की जाती है कि देश की शिक्षा व्यवस्था और खासतौर पर उच्च शिक्षा व्यवस्था इस सामाजिक कार्यसूची को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। हैरानी नहीं होगी कि इनके पांवों तले कुचले जाते रहे तबकों के बीच से तथा उनके हमदर्दों की कुछ गर्म आवाजें पितृसत्ता, जाति व्यवस्था, इतिहास के ब्राह्मणीकरण और मनुवाद को ‘जहर’ बताएं और इसकी काट या एंटी-डोट की तलाश को अपनी विद्वता का लक्ष्य बनाएं। यह सामाजिक क्रांति का वह एजेंडा है, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन पूरा तो नहीं कर सका, पर उसने बलपूर्वक देश के सामने रखा ही नहीं था, ऐसी शक्तियों को भी उन्मुक्त कर दिया था, जो इस एजेंडा को आगे ले जाने वाली थीं।

लेकिन, इसके उलट को क्या कहेंगे?पितृसत्ता के विरोध को, जाति के विनाश की वकालत को, इतिहास के ब्राह्मणीकरण की तथा मनु की आलोचना को ही अगर कोई ‘जहर’ बताए तो? स्वाभाविक रूप से इसका एक ही जवाब हो सकता है— यह तो सामाजिक प्रतिक्रांति का एजेंडा है। नेंद्र मोदी के नेतृत्व में संघ-भाजपा की सरकार के दबे-छुपे ढंग से सामाजिक प्रतिक्रांति की शक्तियों तथा प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने और उससे ज़्यादा खुलेआम सामाजिक क्रांति की प्रवृत्तियों को कमजोर करने को बात तो किसी से छुपी हुई नहीं थी। लेकिन, ऐसा लगता है कि मोदी राज के तीसरे कार्यकाल में सामाजिक प्रतिक्रांति की ताकतों के हाथों में बढ़ते पैमाने शासकीय नीति की बागडोर ही सौंपी जा रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वामपंथी के साथ-साथ अंबेडकरवादी विद्वता/विचारों की मौजूदगी को जांच की सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से सितंबर के आखिर में आयोग मांग, इसी सच्चाई को गाढ़े रंग से रेखांकित करती है।

इस प्रसंग को चूंकि मुख्त्यभार के मीडिया में बहुत हद तक अमदेदवादी काट दिया गया है, जबकि इस मामले में इसी प्रधानमंत्री कार्यालय की हैरान करने वाली सक्रियता स्पष्ट रूप

से देखने को मिलती है, जो पूरे शासन के इस दिशा में प्रवृत्त होने का संकेत देती है, इसलिए हम यहां इस प्रसंग का थोड़े विस्तार से जिक्र करना चाहेंगे। इस प्रकरण की शुरुआत, 26 सितंबर को, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर आए एक गुमनाम ट्वीट से होती है। इस ट्वीट में देश के वर्तमान नीति निर्धारकों को चेताया जाता है कि पितृसत्ता, जाति, ब्राह्मणवाद, मनुवाद की आलोचनाओं का ‘जहर’ युवा दिमागों में भरा जा रहा है, जिसके जरिए वामपंथी जुड़ेली शिक्षण का उपयोग अपनी कतारों में भरती के लिए रंगरूट तैयार करने के लिए कर रही है !

बहरहाल, वामपंथ पर हमले की आड़ में वास्तव में सामाजिक रूप से उत्पीड़ितों, खासतौर पर वंचित जातियों



तथा महिलाओं के अधिकारों तथा उनकी समानता की पुकारों का रास्ता खोलने वाली और उनका रास्ता रोकने वाली मेषाओं को उच्च शिक्षा के दायरे से बहिष्कृत ही करने की आरएसएस की मांग तब पूरी तरह से उजागर हो जाती है, जब उक्त ट्वीट के साथ लगायी गयी सूची में डॉ. अंबेडकर की ‘एन्टिलेशन ऑफ कास्ट’ से लेकर, पेरियार, फुले दम्पति तक के लेखन को उक्त ‘जहर’ के उदाहरण के रूप में गिनाया जाता है। ट्वीट के साथ जोड़ी गयी तस्वीर में पूरी 35 पुस्तकें हैं, जिनमें आसानी से समझ में आने वाले कारणों से, महिला लेखिकाओं की संख्या अनुपातहीन तरीके से ज़्यादा है। यानी यह वामपंथ का नाम लेकर, हर प्रकार की प्रगतिशील धाराओं और खासतौर पर जातिभेद-विरोधी तथा लिंगभेद-निषेधक बराबरी के विचारों को शिक्षा के दायरे से उसी तरह बहिष्कृत करने के प्रयासों का एक उदाहरण है, जिस तरह के हमलों के जरिए ब्राह्मणवाद ने बहुत पुराने जमाने में चार्वाक और आजीवक जैसी भौतिकवादी दार्शनिक धाराओं को हाशिए से भी नीचे

बच्चों के पोषण में डिजिटलीकरण न बने बाधा

ल के वर्षों में लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लक्षित समूहों के लिए चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में भी तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इससे योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता बेहतर हो सकती है, लेकिन तकनीकी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण पात्र व्यक्ति योजना से वंचित रह जाए, तो यह चिंता का विषय है। बच्चों के भोजन और पोषण से जुड़ी योजनाओं में यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देश में बाल कुपोषण अब भी गंभीर समस्या बना हुआ है। ऐसे में आधार, ई-केवाईसी, फेस रिकग्निशन या किसी ऐप की तकनीकी प्रक्रिया के कारण किसी बच्चे का भोजन और पोषण नहीं रुकना चाहिए। तकनीक का इस्तेमाल योजनाओं को बेहतर बनाने और उनकी निगरानी के लिए हो सकता है, लेकिन गरीब, प्रवासी, आदिवासी और दूसरे वंचित परिवारों के बच्चों के लिए ऐसी शर्तें भोजन और पोषण सेवाओं तक पहुंच को और कठिन बना सकती हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 के अनुसार देश में पांच साल से कम उम्र के 29.3 प्रतिशत बच्चे डिगनेपन के शिकार हैं, 19 प्रतिशत बच्चे दुबले हैं और 31.8 प्रतिशत बच्चों का वजन उन की उम्र के अनुसार कम है। पिछले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुकाबले इन संकेतकों में सुधार दर्ज हुआ है, लेकिन करीब हर तीन में से एक बच्चे का उम्र के अनुसार कम वजन होना बताता है कि चुनौती अभी भी बड़ी है। बच्चे के जीवन के शुरुआती दो वर्षों में पर्याप्त और विविध आहार मिलना भी पोषण का महत्वपूर्ण आधार है इसलिए कुपोषण को खत्म करने के लिए बहुआयामी प्रयास जरूरी हैं।

बच्चे के पोषण की बुनियाद गर्भावस्था के दौरान ही पड़ जाती है। गर्भवती महिला को पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिलना, जन्म के बाद स्तनपान, छह महीने के बाद पर्याप्त और विविध पूरक आहार, साफ पानी, संक्रमण से बचाव और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलना बच्चे के विकास से सीधे जुड़े हैं। इसके बाद आंगनवाड़ी और स्कूल में मिलने वाला भोजन आता है। इसलिए कुपोषण सामने आने के बाद बच्चे का वजन बढ़ाने के प्रयासों के साथ उन कारणों पर भी काम करना जरूरी है, जिनके चलते बच्चा कुपोषण का शिकार होता है। इस पूरी व्यवस्था में आंगनवाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण है। गरीब, आदिवासी, दूरदराज और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी पोषण के साथ स्वास्थ्य और शुरुआती देखभाल की व्यवस्था भी है। इसके लिए जरूरत के मुताबिक पर्याप्त आंगनवाड़ी केंद्र, अच्छे भवन, पानी, बिजली और स्वच्छता की सुविधाएं तथा पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता जरूरी हैं। भोजन की गुणवत्ता पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध दाल, मोटे अनाज, सब्जियां और दूसरी पौष्टिक सामग्री से गर्म पका भोजन दिया जा सकता है। स्कूलों में स्थानीय भोजन और किचन गार्ड को बढ़ावा देने के साथ बच्चों में जंक फूड के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के उपाय भी जरूरी हैं।

मां के पोषण और उसकी सामाजिक सुरक्षा का सवाल भी इससे जुड़ा है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिलने का असर मां और बच्चे दोनों के पोषण पर पड़ता है। मातृत्व लाभ की पहुंच बढ़ाने के साथ तीन साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेच और शुरुआती देखभाल की व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। प्रवासी मजदूरों, बेघर और विस्थापित परिवारों के बच्चों के लिए समस्या और

■ राजु कुमार

कठिन है। पहचान या स्थायी पते के अभाव में यदि कोई बच्चा आंगनवाड़ी, स्कूल, भोजन या स्वास्थ्य सेवाओं से बाहर रह जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर पहले से वंचित परिवारों पर पड़ता है। बच्चों के भोजन की व्यवस्था में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने की भी जरूरत है। स्थानीय स्वयं सहायता समूहों, रसोइयों, किसानों, ग्राम पंचायतों, माता-पिता और स्कूल प्रबंधन समितियों को इससे जोड़ने पर भोजन की गुणवत्ता और निगरानी दोनों में मदद मिल सकती है। स्थानीय किसानों से दाल, मोटे अनाज और दूसरी पौष्टिक सामग्री की खरीद बच्चों को स्थानीय और विविध भोजन उपलब्ध कराने के साथ किसानों और स्थानीय आजीविका को भी सहारा दे सकती है। इसके साथ सामाजिक अंकेक्षण, भोजन की स्वतंत्र गुणवत्ता जांच, सरकारी ठेकों में पारदर्शिता और शिकायतों के निवारण की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के भोजन और पोषण की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए निजीकरण के बजाय सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे हुए

स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है। बदलती जलवायु और बा-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का असर परिवारों की खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी या आजीविका का नुकसान अंततः घर में उपलब्ध भोजन को प्रभावित करता

है। इसलिए आपदा के समय बच्चों और गर्भवती महिलाओं के भोजन और पोषण की व्यवस्था को राहत कार्यक्रमों का जरूरी हिस्सा बनाना होगा। स्थानीय कृषि और पोषण योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है। आंगनवाड़ी, आशा और पीएम पोषण से जुड़े फ्रंटलाइन कार्यक्रमताओं को पर्याप्त मानदेय, सामाजिक सुरक्षा, जरूरी संसाधन और काम की बेहतर परिस्थितियां दिए बिना जमीनी स्तर पर पोषण सेवाओं में अपेक्षित सुधार मुश्किल है। भोजन और पोषण से जुड़ी योजनाओं में बढ़ते डिजिटलीकरण को भी इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है, ताकि तकनीक बच्चों तक भोजन और पोषण की पहुंच में बाधा न बने। डिजिटलीकरण के कारण बच्चे की भोजन और पोषण सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बच्चों के निजी आंकड़ों की सुरक्षा का सवाल भी इससे जुड़ा है। दूसरी ओर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों पर डिजिटल रिपोर्टिंग का काम इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि बच्चों के साथ सीधे काम करने का उनका समय कम होने लगे। तकनीक सुविधा और निगरानी का साधन रहे, अधिकार पाने की शर्त नहीं।

भोपाल में हाल में हुए बच्चों के भोजन के अधिकार पर तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में तीन दिनों की चर्चा के बाद जारी पोषण में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। अधिवेशन में प्रख्यात अर्थशास्त्री ज्यूं द्रेज सहित भोजन के अधिकार के लिए लंबे समय से काम कर रहे कई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अधिवेशन में भी इस बात पर जोर दिया गया कि कुपोषण रोकने के प्रयास बच्चे के कुपोषित पाए जाने के बाद ही शुरू नहीं होने चाहिए। मां के पोषण से लेकर बच्चे के शुरुआती आहार, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य सेवाओं और स्कूल तक पोषण की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्रेच और शुरुआती देखभाल को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य, पोषण, मातृत्व सुरक्षा, स्थानीय खाद्य व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को साथ लेकर चलना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि आधार, पहचान या कोई तकनीकी प्रक्रिया किसी बच्चे और उसके भोजन और पोषण के अधिकार के बीच न आए।

आपके पत्र

कैप्टन स्मित ने संकट की घड़ी में दिताया अदम्य साहस

विमान में बैठे यात्रियों के लिए उड़ान का समय सामान्यतः रोमांच और सुविधा का अनुभव होता है, लेकिन जब हजारों फीट की ऊंचाई पर अचानक कोई गंभीर संकट सामने आ जाए तो कुछ ही क्षणों में पूरी स्थिति जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष में बदल सकती है। ऐसे समय में विमान के पायलट की भूमिका केवल विमान उड़ाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी सूझबूझ, धैर्य, निर्णय क्षमता और साहस सैकड़ों लोगों के जीवन की रक्षा का आधार बन जाते हैं। हाल की एक घटना ने एक बार फिर यह साबित किया है कि संकट के सामने मजबूत हौसला और पेशेवर जिम्मेदारी कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। दुबई से इजरायल जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में सामने आए गंभीर खरबे के दौरान कैप्टन स्मित मच्छर ने जिस तरह परिस्थितियों का सामना किया, उससे उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विमान के भीतर अचानक पैदा हुए संकट ने यात्रियों और चालक दल के सामने असाधारण चुनौती

एक विमानन संबंधी कार्यक्रम में भाग

धकेल दिया था।

इस गुमनाम ट्वीट के आने के बाद जो कुछ होता है, वह और भी ज़्यादा मामूखेज है। प्रधानमंत्री कार्यालय इस ट्वीट का स्वतः संज्ञान लेकर, उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में एक चिट्ठी लिखता है और संबंधित विभाग उसी दिन, यानी 27 सितंबर को ही सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को चिट्ठी लिखकर उनसे फौरन इन शिकायतों पर उनका जवाब मांगता है। जाहिर है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय तुरंत इस मामले की समीक्षा में जुट जाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों से इस शिकायत के सिलसिले में पूछा गया एक सवाल और भी ज़्यादा आश्चर्याएं पैदा करने वाला है। उन्हें यह भी बताना है कि उक्त ‘जहर’ फैलाने वाले विचारकों/लेखकों से जुड़े पाठ्यक्रमों में कितने

छात्र हैं। यानी कुल मिलाकर इस जहर के फैलाने और फैलाने का पैमाना कितना है? इसके लिए कितनी और कैसी शेरेंबंदी की जरूरत होगी? शैशव, जातिवाद तथा मर्दवाद के पक्ष में वर्तमान शासन के सीधे हस्तक्षेप का यह पहला उदाहरण हो भी, तब भी इसके पीछे चले आ रहे एक लगातार जारी सिलसिले को याद रखना जरूरी है।। पाठकों को याद होगा कि रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या समेत उच्च शिक्षा संस्थाओं में जातिवादी भेदभाव के अनेक प्रकरणों की पुष्टभूमि में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने आधे-अधूरे तरीके से जो दिशा-निर्देश तैयार किए थे, उनके खिलाफ भी जाहिर है कि संघ परिवार के संगठनों की सलिसता के साथ, विरोध का तुफान खड़ा करने की कोशिश की गयी थी। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी सुनवाई कर, इन दिशानिर्देशों पर रोक ही लगा दी थी।

सर्वण गोलबंदी के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए,

नीट परीक्षाओं की धांधली से भड़के छात्रों और युवाओं के जंतर-मंतर आंदोलन के बाद के दौर में, उसके समानांतर सर्वण युवाओं की लामबंदी की कोशिशों के जरिए, युवाओं को बांटने की कोशिश की गयी थी। और जब यह कोशिश, खास कामयाब नहीं हुई, तब जंतर-मंतर आंदोलन के फौरन बाद, आरक्षण व्यवस्था में सुधार के नाम पर, आरक्षण-विरोधी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गयी। यह दूसरी बात है कि इसका ज़्यादा व्यापक प्रभाव नहीं नजर आया, उल्टे इसके पीछे सत्ताधारी भाजपा तथा संघ के नेताओं का हाथ होने का सच ही उजागर हो गया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के उप-मुख्यमंत्री, बुजेश पाठक खासतौर पर इस बड़े उपाय के पीछे खड़े लोग आ रहे थे और उनकी सरकार इसे छुपाने की कोई कोशिश भी नहीं कर रही थी। इसी खुलमखुल्लापन को अब केंद्र की शिक्षा नीति में अमली मंजिल पर पहुंचा दिया गया है।

यह भी याद रहे कि संघ परिवार पहले से ही जातिवाद तथा लिंगभेद को सच्चाइयों को ही नकारने के जरिए, इन असमानताओं को मिटाने के संघर्षों को ही गैर-जरूरी साबित करने में लगा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसी प्रतिगामी रुख की शासकीय नीति के स्तर पर अभिव्यक्ति में, मोदी सरकार इसके लिए बराबर लड़ती आयी है कि रंगभेद-विरोधी वैश्विक एकजुटता में, भारत के जाति भेद के जिक्र को हर्गिज शामिल नहीं किया जाए। इसी प्रकार, पश्चिमी दुनिया में कुछ शैक्षणिक परिसरों में जहां भारतीय छात्रों की भी टीक-टाक उपस्थिति है, जब भी भेद-भाव विरोधी पहलों के हिस्से के तौर पर, जाति-भेद विरोधी कदमों के शामिल किए जाने की बात आयी है, संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने ही गैर-जरूरी साबित करने में हाथ रखने के जरिए वर्तमान सरकार ने भी, ऐसी सभी कोशिशों का विरोध ही किया है। यह आरएसएस के बुनियादी एजेंडा को ही दिखाता है, जो अपने सारे दिखावे के बावजूद, जातिवादी तथा लिंगभेदी, विशेषाधिकारों का हिमायती ही बना रहा है।

राष्ट्रीय आंदोलन से उन्मुक्त हुई सामाजिक क्रांति को परटने के लिए संघ- भाजपा का प्रतिक्रांतिकारी हमला दो टांगों पर खड़ा है—हिंदू श्रेष्ठतावाद और मनुवाद या ब्राह्मणवाद, जिसमें सर्वणवाद और मर्दवाद दोनों का योग है। शासन के विभिन्न स्तरों तक इस हमले के पहुंचने से सामाजिक प्रतिक्रांति का वास्तविक खतरा पैदा हो गया है। जातिगत तथा लैंगिक समानता समेत, हर तरह की समानता की सोच आज निशाने पर है। कथित दिमागी नक्सलों के खिलाफ युद्ध को वर्तमान संघी सत्ता की पुकार, इसी सामाजिक प्रतिक्रांति का युद्धघोष है।

(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं ।)

ललित सुरजन की कलम से

लक्ष्यवेध पर संदेह क्यों?

‘एक टीकाकार ने लिखा है कि मोदी सरकार ने सड़किल स्ट्रीट के माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला है। ऐसा कोई ऑपरेशन वास्तव में हुआ या नहीं इसे कुछ देर के लिए भूल जाएं। यदि भारत की जनता इस बात से प्रसन्न और आश्चस्त होती है कि मोदी सरकार पाकिस्तान से बदला लेने में सक्षम है व हाथ पर हाथ धरे रहने की बजाय कार्यवाई कर रही है तो यही सही। कुछ अन्य टीकाकारों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि बीते वर्षों में अनेक बार ऐसे सीमित आक्रमण भारत करते रहा है, लेकिन पूर्व में इसका हिंदीओ कभी नहीं पीटा गया। इस संदर्भ में पूर्व प्रसंगों के विवरण भी दिए गए हैं। कहने का आशय यह कि मोदी जो इससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं।’

‘हम मानते हैं कि अगर सचमुच यह लक्ष्यभेदी आक्रमण किया गया था और वर्तमान सरकार इससे लाभ उठा रही है तो यह एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है। किन्तु इसमें अगर सिर्फ प्रचार पाने की चाहत है तो आगे चलकर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं है।’

(देशबन्धु में 06 अक्टूबर 2016 को प्रकाशित)
https://lalitsurjan.blogspot.com/2016/10/blog-post.html

पावन प्रसंग

पितृ तर्पण

भारतीय समाज में धर्म का प्रमुख स्थान रहा है। धर्म का प्रयोग धार्मिक कृत्यों, रीति-रिवाजों, व्रत व त्योहारों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने तथा व्यवित्व विकास में सहायक माना जाता है। इस प्रकार धर्म व्यवस्था से व्यक्तित और समाज अतुष्टासित होता है। भारतीय संस्कृति में माता-पिता को देवतुल्य माना गया है। हमारे संस्कारों में मां के चरणों में ममता, त्याग और करुणा का संसार दिखाई देता है, तो पिता के जीवन में परिश्रम, जिम्मेदारी और सुरक्षा की छाया। मां-बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं। वे अपनी जरूरतें कम कर बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं। उनकी खुशियां बच्चों की मुस्कान में बसती हैं और उनका जीवन परिवार को संवारने में बीत जाता है।

पितृपक्ष; जिसका विशेष महत्व हिंदू धर्म में माना जाता है। पितृ पक्ष में पूर्वजों को विधि-विधान से तर्पण करना पितृ तर्पण कहलाता है। पितृ तर्पण आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिनों तक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज कुटुम्बजनों से मिलने स्वर्ग से धरती पर आते हैं व उन्हें आशीर्ष देते हैं और इसलिए तालाब में जाकर जल अर्पित किया जाता है।

पितृपक्ष में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। पितृपक्ष में कुछ कार्य निषिद्ध माने गए हैं; महिलाओं को नये वस्त्र, नया आभूषण, नई चूड़ी पहनना वर्जित होता है साथ ही गर्म पानी में कपड़े डुबाना, सूप छलनी बजाना, पटक कर कपड़े धोना आदि निषिद्ध होता है। व्यक्ति के मृत्यु के एक वर्ष पश्चात प्रथम बार पितृ तर्पण करने को पितर मिलाना कहा जाता है। सभी पुरुषों की तिथि के अनुसार पितृतर्पण किया जाता है तथा सभी महिलाओं का तर्पण नवमी तिथि के दिन किया जाता है जिसे मातृनवमी कहा जाता है।

पितृपक्ष के पहले दिन को पितरबैसका व अंतिम दिन को पितरखेदा कहा जाता है। पितृपक्ष के प्रथम दिन से पूरे 15 दिनों तक प्रातः चौर के आंगन में गोबर से चौकोर लीपकर चावल के आटे से चौक बनाकर फूल वह भोगी उड़द के दाल को छिड़क कर लोटे में पानी रखा जाता है। बड़ा व पूड़ी का भोग लगाकर भोग लगाया जाता है। बड़ा, पूरी व मालपुआ आदि का छोटा-छोटा टुकड़ा छप्पर में भी रखा जाता है ताकि कौवा व अन्य पक्षी पितर के रूप में आकर ग्रहण करें।

पितृपक्ष के 15 वें दिन पितृ अमावस्या के दिन को पितरखेदा कहा जाता है, इस दिन 15 दिनों का होम, बड़ा, बोबर व पूड़ी को पोटली में बांधकर उसमें पैसे डालकर तालाब में विसर्जित किया जाता है जिससे मछली आदि जीवों को भोजन मिलता है। ऐसा लोकविश्वास है कि-यह सामग्री पितरों को प्राप्त होता है। इस तरह ग्रामीण अंचल में विधि-विधान से पितरों का तर्पण किया जाता है।

डॉ. श्रीमती ज्योति किरण चंद्राकर

खेल जगत

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बुलंद इरादों से उतरेगा

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की कप्तानी श्रेयस अय्यर के हाथों में

■ सत्येन्द्र पाल सिंह

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (देशबन्धु)। श्रेयस अय्यर की अगुआई में भारतीय क्रिकेट टीम 2026 एशियाई खेलों में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को शुक्रवार निशीन(जापान) में थोड़े संघर्ष के बाद 19 रन से हरा अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखने के बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ नवाबों के शहर लखनऊ में पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के मंगलवार को खेले जाने वाले पहले मैच में बुलंद हौसलों के साथ उतरेगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने शे होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज से अपना आखिरी टी-20 मैच इस साल के शुरू में आईसीसी टी-20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर आठ में खेला और संजु सैमसन के अविजित 97 रन से कोलकाता के इंडन गार्डन में चार गेंद के बाकी उर्रमें रहते पांच विकेट से जीत दर्ज की।

वेस्टइंडीज के कप्तान अभी शे होप हैं जबकि भारत की कप्तानी अब श्रेयस अय्यर के हाथ में वह खुद को भारत के नए टी-20 क्रिकेट कप्तान के रूप में जुटे हैं। भारत ने वेस्टइंडीज से अपने पांच में तीन जीते और दो हारे हैं और उसके खिलाफ अपना दबदबा बनाए रखने के मकसद से ही



उतरेगा। संजु सैमसन भारत के लिए एशियाई खेलों में सेमीफाइनल और फाइनल सहित दो मैच खेलने के बावजूद दहाई के अंक तक नहीं पहुंच सके। भारत के सामने बड़ा सवाल यह रहेगा कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अभिषेक शर्मा और 15 बरस के वैभव सूर्यवंशी से ही पारी का आगाज कराए और संजु सैमसन को तीसरे नंबर पर बरकरार रखे। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत संतुलित एकादश के साथ उतरेगा। ऐसे में अपने अनुभव और पिछली बेहतरीन पारी

के चलते बहुत मुमकिन है भारत अभिषेक शर्मा और संजु सैमसन से पारी का आगाज करा कर वैभव सूर्यवंशी को एकादश से बाहर रखे और तीसरे नंबर तब इशान किशन और चौथे पर कप्तान श्रेयस अय्यर, पांचवें पर तिलक वर्मा और फिर् अल्लारुंडर शिवम दुबे, अक्षर पटेल और नीतिश रेड्डी उतरे। भारत के चीफ कोच गौतम गंभीर का जिस तरह से संजु पर भरोसा है उससे उनके वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की एकादश में अपनी जगह बरकरार रखने की उम्मीद है।

आईसीसी ने भारत-वेस्टइंडीज टीम पर लगाया जुर्माना

दुबई। न्यू चंडीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए तीसरे वनडे मुकाबले में स्लो ओवर रेट बनाए रखने के लिए आईसीसी ने भारत और वेस्टइंडीज टीम पर जुर्माना लगाया गया है। शनिवार को हुए आखिरी वनडे में समय की छूट को ध्यान में रखते हुए भारत को चार ओवर और वेस्टइंडीज को दो ओवर कम फेंकने का दोषी पाया गया। इसके बाद भारतीय टीम पर उनकी मैच फीस का 20 प्रतिशत और वेस्टइंडीज पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया।आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 (जो न्यूनतम ओवर-रेट उल्लंघनों से संबंधित है) के अनुसार, अगर कोई टीम तय समय में ओवर नहीं फेंक पाती है, तो उसके खिलाड़ियों पर हर ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।

भारत की 7 सदस्यीय टीम घोषित भुवनेश्वर कुमार संभालेंगे कमान

हॉंगकांग, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। हॉंगकांग सिक्स 2026 के लिए भारतीय टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के स्टार खिलाड़ियों के साथ उतरेगी। इसमें सात प्रमुख भारतीय क्रिकेटर 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेले जाने वाले तेजतर्रार ‘सिक्स-ए-साइड’ (छह खिलाड़ियों वाले) फॉर्मेट में हिस्सा लेंगे। टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड पर खेले जाने वाली इस लीग में भारतीय टीम की कप्तान अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार संभालेंगे। उनके साथ आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कृणाल पांड्या, शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नितिश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी. नटराजन भी होंगे। भुवनेश्वर के पास अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल का कई वर्षों का अनुभव है और वे नई गेंद से असरदार प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, जबकि कृणाल एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर टीम को विविधता देते हैं। नितिश आक्रामक बल्लेबाजी और टॉप ऑर्डर में खेलने का अनुभव लाते हैं। वहीं, शशांक और तेवतिया मैच फिनिश करने की अपनी काबिलियत दिखाते हैं। त्रिपाठी आक्रामक इग्रेडे के साथ खेलते हैं और नटराजन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर एक खास विकल्प देते हैं। टीम इंडिया हॉंगकांग सिक्स में फिर से वापसी करेगी और टूर्नामेंट में आगे तक जाने की कोशिश करेगी। 2025 में उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध डकवर्थ-लुइस नियम से दो रन की जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन बाद के मैचों में हार के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इस बार चुनौती कड़ी होगी। पाकिस्तान 2026 के टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन के तौर पर उतरेगा।

चोट के कारण इस साल कोर्ट पर नजर नहीं आएंगी पोटपोवा

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। दुनिया की 25वें नंबर की खिलाड़ी अनास्तासिया पोटापोवा ने अपने 2026 सीजन को समय से पहले ही खत्म कर दिया है। उन्होंने चोटों से जूझने और करियर की सबसे अच्छी रैंकिंग हासिल करने के मिले-जुले साल के बाद ठीक होने पर ध्यान देने का फैसला किया है।

कि अब रुकने का समय आ गया है। मेरे लिए यह सबसे साफ संकेत है कि मुझे ब्रेक लेने, अपने शरीर को ठीक होने के लिए जरूरी समय देने और मजबूती से वापसी करने की जरूरत है। 2027 में मिलते हैं। ‘पोटापोवा ने यह घोषणा बीजिंग टूर्नामेंट में सिन्ना क्रॉस के खिलाफ अपने शुरुआती दौर के मैच से दाहिने कंधे की चोट के कारण हटने

शरीर को आराम की जरूरत: अनास्तासिया पोटापोवा

के कुछ दिनों बाद की है। उन्हें इसके बाद लुहान में खेलना था, लेकिन अब वह नए सीजन के लिए पूरी तरह फिट होने पर ध्यान देंगी। इस फैसले के साथ ही उस सीजन का समापन हो गया जिसमें पोटापोवा ने रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई। उन्होंने साल की शुरुआत लिज्न से पहले 97वें स्थान पर रहते हुए की थी, लेकिन धीरे-धीरे रैंकिंग में ऊपर चढ़ती गई और आखिरकार करियर की सर्वश्रेष्ठ 25वां रैंकिंग तक पहुंचीं, जो अभी भी उनकी मौजूदा रैंकिंग है। उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन क्ले कोर्ट पर रहा।

वैंक्वर, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। टोरेटो सिक्सर्स ने सोमवार को यहाँ मशहूर बीसी प्लेस में खेले गए पुरुषों के फाइनल में वैंक्वर एंक्स को पांच विकेट से हराकर कनाडा सुपर 60 खिताब जीता। यह टोरेटो की दोहरी जीत है। वह इससे पहले महिलाओं की चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं।

जहीर खान की सह-मालिकाना हक वाली टीम वैंक्वर एंक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 164 का स्कोर बनाया। ओबस पीनार ने 21 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए और कप्तान मोईन अली ने 18 गेंदों पर 45 रन जोड़े, लेकिन टोरेटो ने आखिरी गेंद पर लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट पर 168 रन बनाकर जीत हासिल की। एंक्स ने धमाकेदार शुरुआत की; एनयूरिन डोनाल्ड ने नौ गेंदों पर 17 रन बनाए और एरॉन जॉनसन ने 10 गेंदों पर 14 रन जोड़े। मार्टिन एंड्रसन के शून्य पर आउट होने



के बाद, मोईन और पीनार ने पारी संभाली और दोनों ने मिलकर 21 बाउंड्री लगाईं। पीनार के 82 रन सिर्फ 21 गेंदों पर आए, जिसमें दो चौके और 12 छक्के शामिल थे, जबकि मोईन के 45 रनों में दो चौके और पाँच छक्के शामिल थे। वैंक्वर ने 16.40 के रन रेट से 164/3 का स्कोर बनाया। टोरेटो की ओर से लक्ष्य का पीछा निकोलस पून ने किया, जिन्होंने 23 गेंदों पर 67 रन बनाए। उनकी पारी में दो चौके और नौ छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट ‘प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट’ भी चुना गया। 291.30 रहा। कीरोन पोलार्ड ने 13 गेंदों

मार्टिन एंडरसन के शून्य पर आउट होने के बाद, मोईन और पीनार ने पारी संभाली

पर 35 रन जाड़े, जबका डेनयल सम्स नौ गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाकर लौटे (जिसमें तीन छक्के शामिल थे), जिससे टोरेटो मुश्किल लक्ष्य के साथ तालमेल बिठाए रहा। विल स्मीड ने भी सात गेंदों पर 16 रन बनाए, जिसके बाद लुईस ग्रेगरी ने उन्हें आउट कर दिया। पून की आक्रामक बल्लेबाजी ने टोरेटो को जरूरी रन रेट से काफी आगे पहुँचा दिया, जिसके बाद पोलार्ड और सैम्स ने सुनिश्चित किया कि अंत में कोई गड़बड़ न हो; सिक्सर्स ने आखिरी गेंद पर 168/5 रन बनाकर पाँच विकेट से जीत हासिल की। पून को पूरे टूर्नामेंट में 207 रन बनाने और दो विकेट लेने के लिए ‘प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट’ भी चुना गया।

एशियन गेम्स : वैश्विक खेल मंच पर चमके भारत के सितारे

■ विश्वास कैलाश सांरग

जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा की चमक को पूरी दुनिया ने देखा है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और जज्बे का शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती खेल शक्ति का परिचय कराया। तिरिगे की आन, अब और शान के लिए मैदान में उतरे हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में भारत को गौरवपूर्ण चौथा स्थान दिलाया। यह उपलब्धि केवल पदकों की संख्या नहीं बल्कि भारत की युवा खेल प्रतिभा के निरंतर निरखते सामर्थ्य और वैश्विक खेल मंच पर बढ़ते प्रभाव की स्वर्णिम चमक है। वहीं इस प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने 10 मेडल जिनमें 5 स्वर्ण, 4 रजत 1 कांस्य पदक अर्जित कर अपनी सर्वोच्च प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर विशेष योगदान दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज खेल भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं केंद्रीय खेल

मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में खेलो इंडिया जैसी योजना के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने, प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके पास अब केवल प्रतिभा नहीं बल्कि उसे निखारने के लिए अवसर, प्रशिक्षण और प्रतियस्पर्धी वातावरण भी उपलब्ध हो रहा है। मध्यप्रदेश में भी हम प्रधानमंत्री के विजन को दृष्टिगत रखते हुए एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान के उन्नयन व विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकादमी संचालित हैं। इन अकादमियों में विश्व स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। नवीन सीएम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना के तहत प्रदेश की सभी 230 विधानसभा में खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। खेलो हमपी यूथ गेम्स, पार्थ योजना, खेलो बढ़ो अभियान, टैलेंट सर्च, समर कैंप सहित अन्य आयोजनों के माध्यम से नई प्रतिभाओं की तलाश और उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।



इस प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ियों ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर विश्व पटल पर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। भारत के कुल पदकों में एथलेटिक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसमें कुल 24 पदक जीते गए। इसके बाद शूटिंग का नंबर रहा, जिसमें 15 पदक मिले। इनमें तीन बार खिलाड़ी टॉप पोडियम पर रहे। बॉक्सिंग में भी 3 स्वर्ण पदक मिले, जिनमें लक्वीना बोरोहोम भी शामिल थीं। आचरी में सबसे ज्यादा 5 बार खिलाड़ी शीर्ष पोडियम पर रहे। अमन सहरावत और सुजीत कलकल ने रसलिंग में एशियन गेम्स चैंपियन का खिताब जीता। भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी टीमों ने गोल्ड मेडल हासिल किए। नीरू ढांडा, कुमकुम मोहोद, गुलवीर सिंह और विथ्या रामराज जापान में भारत के प्रमुख प्रदर्शन करने वाले एथलीट में शामिल रहे, जिन्होंने कई पदक जीतने में योगदान दिया।

वहीं मध्यप्रदेश के खिलाड़ी भी इस गौरवमयी उपलब्धि में अहम योगदान दिया। मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने शूटिंग (शॉटगन) के वुमंस ट्रैप इंडिविजुअल में स्वर्ण, ट्रैप मिक्सड टीम में स्वर्ण और वुमंस

लिस्बन। पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कोच जॉर्ज जीसस ने स्टार खिलाड़ी के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ विवाद को गलतफहमी करार देते कहा है कि उनके लिए राष्ट्रीय टीम के दरवाजे खुले हैं। रविवार को नर्वे पर 2-1 से धरलू जीत के बाद जीसस ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर वह चाहेगा, तो वह राष्ट्रीय टीम में वापस आ जाएगा। हम अगले कॉल-अप से पहले बात कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला क्रिस ही करेंगे। मैंने कहा, ‘मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरे करीब रहो, चाहे तुम खेल रहे हो या नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है।’ और अब मैं वही बात कह रहा हूं।’ जीसस के इस बयान ने रोनाल्डो के लिए पुर्तगाल की राष्ट्रीय में वापसी के रास्ते खोल दिये है। उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर को नेशंस लीग में नर्वे के खिलाफ 2-1 से मिली जीत में रोनाल्डो की एक स्थानापन्न के रूप में रखने के जीसस के फैसले ने सार्वजनिक विवाद को जन्म दिया। इसके बाद रोनाल्डो ने पुर्तगाल टीम का शिविर छोड़ दिया था।



वैभव को अपने मौके का इंतजार करना होगा : गंभीर

■ सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने



नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (एजेंसियां)। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया है। गंभीर ने कहा कि उन्होंने 15 वर्षीय खिलाड़ी को समझाया कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, कभी-कभी खिलाड़ी को अपने मौके का इंतजार करना पड़ता है। इस साल जुलाई में सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने। उन्होंने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना टी-20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और सचिन तेंदुलकर का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ा। इसके बाद, वह पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 साल और 118 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। हालाँकि, उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी सीरीज और एशियन गेम्स से पहले जापान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला। 15 साल के इस बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारत की प्लेइंग इलेवन में वापसी की, जहां उन्होंने 21 गेंदों पर 38 रन बनाकर मैच में अहम भूमिका निभाई। गंभीर ने ‘जियोस्टर’ पर कहा, ‘यह मेरे लिए भी एक नया अनुभव था। हां, वह अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि कभी-कभी, उन खिलाड़ियों की वजह से जिन्होंने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें अपने मौके का इंतजार करना पड़ सकता है। एक और बात,

सोशल मीडिया या बाहर की बातें प्लेइंग इलेवन तय नहीं करतीं। भारतीय मुख्य कोच ने आगे कहा, ‘यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रैसिंग रूम का समीकरण कैसा है, कौन सा खिलाड़ी कोच और कप्तान को मैच जिताने की क्षमता रखता है, तथा टीम की सबसे मजबूत ‘प्लेइंग इलेवन’ क्या है। इसके साथ ही यह भी देkhना होता है कि किसने लंबे समय तक लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर आज हम वैभव को मौका देते हैं, तो मेरे और टीम से बाहर होने वाले खिलाड़ी- चाहे वह अभिषेक हों या संजु सैमसन के बीच बातचीत काफी मुश्किल होगी। ‘उन्होंने आगे कहा, ‘यही वजह है कि हम अचानक उस टीम संयोजन (कॉम्बिनेशन) को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसने पिछले डेढ़-दो साल में शानदार प्रदर्शन किया है। लगातार तीन-चार मैचों में असफल होने पर हम अनुभवी खिलाड़ियों को ड्रॉप करके किसी ऐसे युवा को टीम में शामिल नहीं कर सकते, जो भले ही बेहद प्रतिभाशाली और बेहतरीन फॉर्म में हो। खिलाड़ियों को कभी-कभी अपने मौके का इंतजार करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रैसिंग रूम में सुरक्षा और निरंतरता का माहौल बनाए रखना है।

सार संक्षेप

ब्राजील से मिली हार के बाद भारत के सामने उरुग्वे की कड़ी चुनौती

कोलकाता। ब्राजील से 0-4 की हार से उबरने के लिए भारत के पास बहुत कम समय है उसे अब मंगलवार को यहां फीफा अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे जैसी मजबूत टीम का सामना करना है। पनामा के खिलाफ 1-1 से ड्राँ मैच ने खालिद जमील की टीम के लिए अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन शनिवार को साउट लेक स्टेडियम में ब्राजील ने भारत और दुनिया की टॉप टीमों के बीच कौशल का अंतर दिखा दिया। भारत को अब उस हार को पीछे छोड़कर उरुग्वे के खिलाफ मुकाबला करने का तरीका खोजना होगा, जो दुनिया में 20वें नंबर पर है। बड़ी हार के बावजूद, जमील को अपनी टीम के प्रदर्शन में कुछ सकारात्मक बातें दिखीं, खासकर उनकी पॉसिंग, डिफेंस का तालमेल और शुरुआती 25 मिनट में काउंटर-अटैक करने की कोशिशें। ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने भी उन क्षेत्रों में भारत की कोशिशों को माना। भारत को उन पलों को आगे बढ़ाना होगा, खासकर ऐसी टीम के खिलाफ जिसके पास बहुत अधिक अंतरराष्ट्रीय अनुभव है। दुनिया में 138वें नंबर की टीम के लिए, उरुग्वे के खिलाफ गोल कराना या मैच ड्राँ कराना भी एक बड़ी उपलब्धि होगी।

न्यूजीलैंड के लिए ‘केजुअल’ कॉन्ट्रैक्ट पर खेलेंगे माइकल ब्रेसवेल

क्राइस्टचर्च। न्यूजीलैंड के अनुभवी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल ने 2026-27 सीजन में ऑस्ट्रेलिया की विज बेश लीग (बीबीएल) में खेलने का मौका पाने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ ‘केजुअल’ कॉन्ट्रैक्ट लेने का फैसला किया है। इस कदम से वह दुनिया भर की टी20 लीगों में खेलने के लिए अधिक उपलब्ध रहेंगे, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि उनकी प्राथमिकता अभी भी न्यूजीलैंड की नेशनल टीम के लिए खेलना ही है। 35 वर्षीय ब्रेसवेल उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने 2026-27 सीजन के लिए केजुअल कॉन्ट्रैक्ट चुना है। इस सूची में फिन एलन, मार्क चैपमैन, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने और टिम सीफर्ट जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। ब्रेसवेल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने के बाद उनकी जगह बल्लेबाज निक केली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यह केली के करियर का पहला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जो उन्हें अपने फर्स्ट-क्लास डेब्यू के करीब 11 साल बाद मिला है। 33 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है।

नेशंस लीग: पुर्तगाल ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह

नई दिल्ली। पुर्तगाल ने यूईएफए नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना खेल रही पुर्तगाल टीम ने 79वें मिनट में गोकालो रामोस के विजयी गोल की मदद से नॉर्वि को 2-1 से हराया। क्रिस्टोफर अजेर ने शानदार हाफ-बॉली के जरिए मेहमान टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन दो मिनट बाद ही जोआओ कैंसेलो ने शानदार अंदाज में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद मेजबान टीम ने बढ़त हासिल कर ली। जोआओ फेलिक्स के शानदार पास पर गोंकालो रामोस ने गोल दागा। दो बार नेशंस लीग का खिताब जीत चुकी पुर्तगाल की टीम ने मैच के अंत तक अपनी बढ़त कायम रखी और ग्रुप ए4 में जीत का सिलसिला जारी रखा। हालांकि, मैच के आखिरी मिनटों में फ्रांसिस्को कॉन्बेकाओ को दूसरा पीना कार्ड मिलने के कारण मैदान छोड़ना पड़ा, लेकिन इससे टीम की जीत पर कोई असर नहीं पड़ा।

सार समाचार

नटेरन में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं लर्निंग लाइसेंस शिविर

विदिशा, देशबन्धु। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन कार्यालय, विदिशा द्वारा शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नटेरन में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं लर्निंग लाइसेंस शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 200 लाभार्थियों ने सहभागिता की। शिविर में विद्यार्थियों एवं आमजन को यातायात नियमों के पालन, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने तथा सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही लर्निंग लाइसेंस की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति रही।

राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल एवं मलखंब प्रतियोगिता का शुभारंभ आज

विदिशा, देशबन्धु। जिला खेल परिसर में आयोजित होने वाली 70वीं राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल एवं मलखंब प्रतियोगिता की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए 90 नियमित, खेल एवं अतिथि खेल शिक्षकों को दायित्व सौंपे गए हैं। प्रतियोगिता में प्रदेशभर से लगभग 450 खिलाड़ी, 80 कोच एवं मैनेजर तथा 50 स्टेट ऑफिशियल शामिल होंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ 6 अक्टूबर को होगा। इससे पूर्व शाम 5 बजे खिलाड़ियों द्वारा नशामुक्ति एवं खेल जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जो माधवगंज से प्रारंभ होकर महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होते हुए जिला खेल परिसर पहुंचेगी। खिलाड़ियों के ठहरने, परिवहन एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

2 डॉक्टरों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना

जबलपुर, देशबन्धु। हाईकोर्ट ने पीजी मेडिकल छात्रों की याचिका को गलतफहमी पर आधारित मानते हुए निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने खंडवा मेडिकल कालेज के दो डाक्टरों पर कुल 20 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है। दोनों को 10-10 हजार रुपये चार सप्ताह में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में जमा करने होंगे। याचिकाकर्ताओं ने थीसिस गाइड 4A, सौंभ जैन के खंडवा से मंदसौर स्थानांतरण का हवाला देते हुए नया गाइड नियुक्त करने और थीसिस जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि गाइड के स्थानांतरण से शोध कार्य प्रभावित हो रहा है। सुनवाई के दौरान रिकार्ड से सामने आया कि डा. जैन को स्थानांतरण के बाद भी दोनों छात्रों का थीसिस मार्गदर्शन जारी रखने को अनुमति मिली हुई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे साबित हो कि डा. जैन ने मार्गदर्शन करने से इनकार किया हो। कोर्ट ने पाया कि खंडवा मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में अन्य प्रोफेसर उपलब्ध नहीं था, इसलिए डा. जैन को ही मार्गदर्शन जारी रखने को अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि छात्रों के सामने केवल मंदसौर जाकर गाइड से मार्गदर्शन लेने की व्यावहारिक कठिनाई थी। इसे गाइड की अनुपलब्धता बावबर याचिका दायर करना उचित नहीं था। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि याचिका के कारण मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट तक जारी करने की स्थिति बनी।

विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना उचित नहीं

जबलपुर, देशबन्धु। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में विवाहित पुत्री के अनुकंपा नियुक्ति आवेदन को केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर अस्वीकार किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ने विभाग को प्रकरण में नियमानुसार पुनर्विचार कर पात्रता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी व सुमित्रा तिवारी ने पैरवी की। विभाग ने याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति आवेदन को अस्वीकार कर दिया था, जिसके विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। न्यायालय ने मामले के तथ्यों और लागू विधिक प्रावधानों पर विचार करते हुए विभाग के अस्वीकृति आदेश को निरस्त कर दिया। अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी ने बताया कि निर्णय उन विवाहित पुत्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें केवल विवाह हो जाने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का निर्णय समानता और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करता है।

नवरात्रि में मांस-मछली की दुकानें बंद रखने बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन

सिरोंज, देशबन्धु। आगामी श्री नवदुर्गा उत्सव को लेकर नगर में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग को लेकर बजरंग दल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन जिला संयोजक जगदीश शाव्य के नेतृत्व में सौंपा गया।

ज्ञापन में बताया गया कि श्री नवदुर्गा उत्सव 11 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। नवरात्रि के दौरान नगर के विभिन्न स्थानों पर माता रानी के पंडाल लगाए जाते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसे

देखते हुए नगर में साफ-सफाई, यातायात और कानून-व्यवस्था की बेहतर व्यवस्था कराने की मांग की गई। बजरंग दल ने नवरात्रि के दौरान नगर में संचालित मांस-मछली की दुकानों को निर्धारित अवधि तक बंद रखने के आदेश जारी करने की मांग की। साथ ही शराब की दुकानों तथा अन्य स्थानों पर होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखने और अवैध शराब की बिक्री व उपयोग पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में नवीन बस स्टैंड क्षेत्र में अव्यवस्थित रूप से संचालित

दुकानों एवं अतिक्रमण की ओर भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर उचित कार्रवाई की मांग रखी गई। संगठन ने धार्मिक आयोजन स्थलों के आसपास विशेष स्वच्छता व्यवस्था कराने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा आवश्यक इंतजाम किए जाने की मांग की। जिला संयोजक जगदीश शाव्य ने प्रशासन से नवरात्रि पर्व शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कराने की मांग की, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण एवं धार्मिक वातावरण में माता की आराधना कर सकें।

राज्य स्तरीय अंडर-14 हॉकी प्रतियोगिता के लिए सिरोंज के खिलाड़ी रवाना



सिरोंज, देशबन्धु। 70वीं राज्य स्तरीय अंडर-14 बालक हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सांदीपनि स्कूल सिरोंज के चार खिलाड़ी मंगलवार को मंदसौर के लिए रवाना हुए। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 10 अक्टूबर तक मंदसौर में किया जा

रहा है।

प्रतियोगिता में सांदीपनि स्कूल सिरोंज के अजय अहिरवार, प्रदुम, रिजवान मंसूरी और मोहम्मद शाह का चयन हुआ है। खिलाड़ी पहले जेडी कार्यालय भोपाल के लिए रवाना हुए, जहां से अपने दल के कोच एवं मैनेजर के साथ प्रतियोगिता स्थल मंदसौर पहुंचेंगे।

खिलाड़ियों के साथ कोच ऋषि कुशावाह भी रवाना हुए। खिलाड़ियों के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रतीक मेहरा, प्राचार्य महेश ताम्रकार, खेल शिक्षक शान मियां, जमशेद खान, केशव शर्मा, रितेश केवट, शिवम भास्कर सहित विद्यालय स्टाफ ने शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अभियानों के उद्देश्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

विदिशा, देशबन्धु। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न शासकीय अभियानों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार योजनाओं एवं अभियानों के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रहें, बल्कि इनके निर्धारित उद्देश्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर गुप्ता ने सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय अभियानों के उद्देश्यों की प्राप्ति में किसी भी स्तर पर चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान संबंधित अभियानों से जुड़े एक भी आवेदन प्राप्त न हों, इसके लिए मैदानी स्तर

अवैध दवाखाने पर राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई

विदिशा, देशबन्धु। कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिले में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक एवं बिना वैध दस्तावेजों के चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में सोमवार 5 अक्टूबर को राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा ग्राम सिरनोटा में कार्रवाई की गई।

संयुक्त दल ने ग्राम सिरनोटा में उमेश यादव द्वारा संचालित क्लिनिक का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान क्लिनिक में उपचार के लिए पांच मरीज

अभियानों के क्रियान्वयन एवं लंबित आवेदनों की कलेक्टर ने की समीक्षा



पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजना और अभियान का लाभ पहुंचाना ही अभियानों का वास्तविक उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों को शत-प्रतिशत सेचुरिटी की दिशा में गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित

किया कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान वे केवल अपने विभाग के कार्यों तक सीमित न रहें, बल्कि अन्य विभागों से संबंधित गतिविधियों और समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त करें। उन्होंने विशेष रूप से स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे, इसके लिए सभी विभागों

सिरनोटा में क्लिनिक सील, एफआईआर दर्ज कराने पत्र प्रेषित

मौके पर पाए गए। क्लिनिक संचालन एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उमेश यादव से जानकारी एवं दस्तावेज मांगे गए, लेकिन उनके द्वारा क्लिनिक संचालन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। मौके पर की गई जांच एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संयुक्त दल द्वारा पंचनामा तैयार किया गया तथा क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई की गई। साथ ही नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी

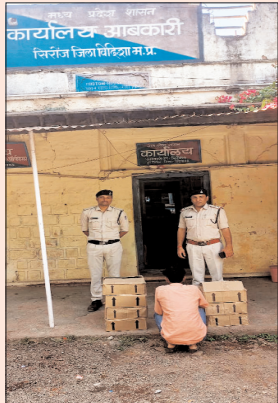
विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु समुदायों के लिए 7 स्थानों पर विशेष शिविर लगेंगे

विदिशा,देशबन्धु। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु समुदायों के नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने तथा दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्र संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिले में अक्टूबर माह में विशेष समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों में जाति प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा।

शिविर 7 अक्टूबर को सूर्यनगर (शमशाबाद), 8 अक्टूबर को नटेरन, 14 अक्टूबर को गुलाबगंज, 15 अक्टूबर को लक्ष्मीनगर (अहमदपुर), 21 अक्टूबर को ग्यारसपुर तथा 28 अक्टूबर को खामखेड़ा में आयोजित होंगे। सभी शिविर प्रातः 11 बजे से निर्धारित स्थल पर शुरू होंगे। नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी समस्याओं एवं आवेदनों का निराकरण कराएं।

विदिशा, देशबन्धु। अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने सोमवार को सिरोंज क्षेत्र में कार्रवाई की। टीम ने ग्राम आन्धरेला में कार्रवाई करते हुए 63 बल्क लीटर अवैध देशी शराब जब्त की।

आबकारी विभाग की टीम ने सिरोंज थाना मुगलसराय क्षेत्र के ग्राम आन्धरेला में ग्राम निवासी अवधेश मालवीय के कब्जे से 200 पाव प्लेन एवं 150 पाव मसाला देशी मदिरा बरामद की। कुल 7 पेटियों में 63 बल्क लीटर शराब मिली। टीम ने शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया। कार्रवाई के दौरान आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कार्रवाई आबकारी उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में की गई। इस दौरान आबकारी आरक्षक मनोज नामदेव एवं नीरज रघुवंशी मौजूद रहे। जिला आबकारी अधिकारी का भी सिरोंज क्षेत्र में दौरा रहा। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के खिलाफ लगातार निगरानी और कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।



कार्यलय आबकारी विभाग में प्र

विशेष अभियान से जिले के साढ़े 11 हजार स्कूली बच्चों के बने जाति प्रमाण पत्र

विदिशा, देशबन्धु। जिला प्रशासन द्वारा जिले की सभी तहसीलों में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए विशेष अभियान संचालित किया गया। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशों में प्रारंभ किए गए इस अभियान के सकारात्मक एवं सफल परिणाम सामने आए हैं। अभियान के तहत जिले की सभी तहसीलों के कुल 11,693 बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं यह जानकारी आज कलेक्ट्रेट के बेतवा सभाकक्ष में आयोजित लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की गई। इस विशेष मुहिम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को भविष्य में शैक्षणिक एवं शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराना था। जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों एवं राजस्व विभाग की सक्रिय भूमिका के कारण जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत बच्चों के शत-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र तैयार किए जा चुके हैं।

हल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों का निर्धारित समयवाधि में समाधान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने 100 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की विशेष समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरणों में एल-1 एवं एल-2 स्तर पर आवश्यक जिला स्तरीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव के संज्ञान में ऐसे प्रकरणों को लाने के लिए डीईओ पत्र तैयार कराने के निर्देश जिला नोडल अधिकारी को दिए। बैठक में वीसी के-मध्यम से खंड स्तर से भी अधिकारी जुड़े रहे। कुरवाई अनुभाग से जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सुरभि तिवारी, शमशाबाद अनुभाग से अपर कलेक्टर श्रीमती मीना मसराम, सहित बासीदा, लटेरी, सिरोंज और ग्यारसपुर अनुभाग से अधिकारी बैठक में जुड़े।

आईआईएम इंदौर के विद्यार्थियों का ग्रामीण अध्ययन दल विदिशा पहुंचा

प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभाव एवं ग्रामीण परिवेश का करेंगे मैदानी अध्ययन

विदिशा, देशबन्धु। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर के 24 विद्यार्थियों का दल स्‍रूल एग्रीजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पांच दिवसीय आवासीय ग्रामीण अध्ययन भ्रमण पर विदिशा जिले में पहुंचा है। विद्यार्थी 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जिले की जनपद पंचायत विदिशा एवं जनपद पंचायत गंजबासौदा के चयनित ग्रामों में प्रवास कर ग्रामीण विकास की जमीनी स्थिति, ग्रामीण जीवनशैली तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभाव का मैदानी अध्ययन करेंगे।

ग्रामीण अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत आईआईएम इंदौर के विद्यार्थियों को छह-छह के समूहों में विभाजित किया गया है। जनपद पंचायत विदिशा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनपुरा एवं करारिया लक्षरपुर तथा जनपद पंचायत गंजबासौदा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेठ एवं निवोदिया को अध्ययन के लिए



चयनित किया गया है। विद्यार्थी इन ग्रामों में रहकर ग्रामीण परिवारों के साथ संवाद एवं प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से गांवों की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को समझेंगे। ग्रामीण अध्ययन दल का विशेष फोकस प्रधानमंत्री आवास योजना के

हितग्राहियों पर रहेगा। विद्यार्थी हितग्राहियों से सीधे संवाद कर पक्का आवास मिलने से पहले परिवार की आवासीय एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा आवास निर्माण के बाद जीवन में आए बदलावों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत परिवार के रहन-सहन, जीवन स्तर,

सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिति तथा आवास की उपलब्धता से हुए सकारात्मक प्रभावों को समझने का प्रयास किया जाएगा।

विद्यार्थियों द्वारा योजना के क्रियान्वयन की जमीनी प्रक्रिया, हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ तथा ग्रामीण स्तर पर योजना से संबंधित अनुभवों की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इस अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को ग्रामीण विकास योजनाओं के वास्तविक प्रभाव को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा। ग्रामीण प्रवास के दौरान विद्यार्थी केवल शासकीय योजनाओं का अध्ययन ही नहीं करेंगे, बल्कि ग्रामीण परिवेश, स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक संरचना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी करीब से जानेंगे। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित होने वाली गतिविधियों और पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए

स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से संवाद करेंगे। इस दौरान विद्यार्थी ग्रामीण समुदाय के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं, चुनौतियों तथा विकास की संभावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। पांच दिवसीय आवासीय प्रवास विद्यार्थियों को कक्षा में प्राप्त प्रबंधन एवं विकास संबंधी अवधारणाओं को ग्रामीण परिस्थितियों के प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ने का अवसर प्रदान करेगा।

जिला पंचायत कार्यालय में परिचय एवं मार्गदर्शन

आईआईएम इंदौर के विद्यार्थियों के विदिशा आगमन पर जिला पंचायत कार्यालय में जनपद पंचायत विदिशा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गगन वाजपेयी एवं जिला समन्वयक (अधिकां) श्रीमती सविता जैन ने विद्यार्थियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने विद्यार्थियों को जिले की भौगोलिक स्थिति, ग्रामीण परिवेश

तथा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा से अवगत कराया। उन्होंने अध्ययन दल को चयनित ग्रामों में भ्रमण के दौरान हितग्राहियों एवं ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने तथा ग्रामीण परिस्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से समझने के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की।

ग्राम पंचायतों के माध्यम से की गई आवश्यक व्यवस्थाएं विद्यार्थियों के ग्रामीण प्रवास को सुगम बनाने तथा अध्ययन दल एवं संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ब्लॉक समन्वयक धर्मेद्र जाट, ज्ञान सिंह लोधी एवं एडीईओ हेमंत धोटे दलों के साथ उपस्थित रहे। संबंधित ग्राम पंचायतों के माध्यम से विद्यार्थियों के ठहरने तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री आज युवाओं से करेंगे संवाद

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव–2026 में प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इसका उद्देश्य युवाओं को नई दिशा, प्रोत्साहन और अवसर उपलब्ध कराना है। कॉन्क्लेव में प्रदेश से 20 हजार से अधिक युवा सहभागिता करेंगे। इस आयोजन में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े अवसरों की जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। डॉ. यादव युवाओं से संवाद कर उनकी आकांक्षाओं, विचारों और अपेक्षाओं को जानेंगे तथा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विकास पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। इस मौके पर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्द्र सिंह परमार भी उपस्थित रहेंगे। कॉन्क्लेव में आईआईटी मुंबई और आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ युवाओं को शिक्षा, तकनीकी विकास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। एम्स के मनोचिकित्सक मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। कॉन्क्लेव में युवाओं के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रसिद्ध पार्श्व गायक सुबिन नीटियाल तथा कबीर कैफे द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जो कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेंगी। कॉन्क्लेव में 17 शासकीय विभागों एवं विभिन्न संस्थाओं की सहभागिता रहेगी। उच्च शिक्षा, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्रम, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, परिवहन, आयुष तथा पुलिस एवं साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न विभाग युवाओं को अपने–अपने क्षेत्र से संबंधित योजनाओं, अवसरों और गतिविधियों से परिचित कराएंगे।

देवड़ा और टेटवाल ने सुनी समस्याए, निराकरण के लिए निर्देश

भोपाल, देशबन्धु। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं मंत्री गौतम टेटवाल ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याओं एवं सुझावों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जिन प्रकरणों में विभाग की कार्यवाई आवश्यक है, उन्हें शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। उप मुख्यमंत्री और मंत्री टेटवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त जनसमस्याओं का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर उसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। आमजन की जनसमस्याओं का समाधान और उन्हें शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के नेतृत्व में संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

भीषण गर्मी ने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़े

सुरेश एस डुमगर

जम्मु, देशबन्धु। कश्मीर में रविवार को असामान्य रूप से भीषण गर्मी पड़ी, कई मौसम स्टेशनों ने अक्टूबर के उच्चतम या लगभग उच्चतम तापमान दर्ज किए क्योंकि पारा मौसमी औसत से काफी ऊपर चढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अक्टूबर माह में शहर में दर्ज किया गया दूसरा सबसे अधिक तापमान है।

यह तापमान 2 अक्टूबर, 2008 को दर्ज किए गए पिछले अक्टूबर के उच्चतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। श्रीनगर में अक्टूबर का अब तक का सबसे अधिक तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस है, जो 2 अक्टूबर, 1931 को दर्ज किया गया था। काजीगुंड में तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने 1 अक्टूबर, 1985 को दर्ज किए गए पिछले अक्टूबर के रिकार्ड 31.2 डिग्री सेल्सियस को तोड़ दिया। तापमान सामान्य से 7.3 डिग्री अधिक

कूनों में गूंजी चीतों की नई पीढ़ी की किलकारी



भोपाल, देशबन्धु। मध्यप्रदेश के ख्योपुर स्थित कूनों राष्ट्रीय उद्यान में चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत 5 अक्टूबर सोमवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई। भारतीय धरती पर जन्मी 32 माह की मादा चीता केजेपी-21 ने 5 स्वस्थ शавकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही भारत में चीतों की संख्या बढ़कर अब 60 हो गई है, इसमें से 41 भारतीय धरती पर जन्में चीते शामिल है। भारत में जन्मी मादा चीता केजेपी-12 और मुछी के बाद केजेपी-21 तीसरी मादा चीता है, जिसने भारतीय

धरती पर शавकों को जन्म दिया। यह उपलब्धि देश में चीता संरक्षण एवं पुनर्स्थापना के प्रयासों की सफलता और चीतों की नई पीढ़ी की विस्तार की दिशा में मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रोजेक्ट चीता से जुड़े वन्य अधिकारियों, पशु चिकित्सकों, मैदानी अमले, प्रबंधन टीम तथा सभी सहयोगियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नन्हें मेहमानों के आगमन से कूनों की धरती पर एक बार फिर वन्य जीव संरक्षण की नई उम्मीद ने जन्म लिया है।

रानी दुर्गावती के मार्ग पर जनजातीय विकास का नया अध्याय

खालवा में 6 सांदीपनि विद्यालय, हरसूद में 490 सीटर कन्या छात्रावास

भोपाल/ खंडवा, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वीरांगना रानी दुर्गावती के दिखाए मार्ग पर मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के विकास का नया अध्याय लिख रही है। रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती पर खंडवा जिले के हरसूद क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कई घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खालवा तहसील में 6 नए सांदीपनि विद्यालय बनाए जाएंगे। हरसूद में 490 सीटर कन्या छात्रावास बनेगा, जबकि करीब

161 करोड़ रुपए की लागत से 40 नए जनजातीय छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों में 34 करोड़ रुपए की लागत से रोटी मेकर मशीनें, वॉटर कूलर और ई–लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आश्रम स्कूलों के विकास के लिए 143 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने खंडवा में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हाइटेक नर्सरी और जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने की घोषणा की।

जनजातीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से जुड़े कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। करवानी उद्हन सिंचाई परियोजना पर भी तेजी से काम करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने खंडवा सहित 6 जिलों के 3 लाख 54 हजार 126 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 21.34 करोड़ रुपए

से अधिक की बोनस राशि अंतरित की। खंडवा वन मंडल की 56 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के 26,400 से अधिक हितग्राहियों को 4.58 करोड़ रुपए का काष्ठ लाभांश भी वितरित किया।

इस अवसर पर 52 गढ़ों के राजवंशजों का पहली बार सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने क हा कि रानी दुर्गावती का जीवन स्वार्थिमान, नारी शक्ति, जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता की प्रेरणा देता है।

उन्होंने खंडवा जिले में करीब 143 करोड़



रुपए की लागत के 18 विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रीवा एवं मऊगंज में सेवा कार्यों में हुए शामिल, कहा

किसानों को हर सुविधा उपलब्ध करा रही सरकार

रीवा/भोपाल, देशबन्धु। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने सोमवार को रीवा एवं मऊगंज जिले के प्रवास के दौरान सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न सेवा कार्यों में सहभागिता की। उन्होंने बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता भाजपा की विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाकर संगठन को और मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को गोलियों से भूना गया था। भाजपा सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण करने के साथ हर सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब

परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने का संकल्प लिया है। गरीब के सिर पर पक्की छत हो, उसका बैंक खाता हो, उसे आयुष्मान योजना का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिले, उज्ज्वला योजना के माध्यम से धुएँ से मुक्ति मिले और घर में शौचालय हो, इन संकल्पों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन



यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार का निरंतर प्रयास है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी जरूर तम दं व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया कहा आप बच्चों और उनके परिवारों की चिंता करें, क्योंकि आपके प्रयास आने वाली पीढ़ी के भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं। स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज और मजबूत भारत का

निर्माण करेंगे। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी संबोधित किया।

बैठक में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह, संभाग प्रभारी विजय दुबे, जिला प्रभारी शशांक श्रीवास्तव, सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र मिश्रा, विधायक गिरीश गौतम, प्रदीप पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, सिंगरौली विकास प्राधिकरण अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, विध्य विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉ. अजय सिंह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखण्ड प्रताप सिंह, मृगेंद्र सिंह सहित पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

10 विमानतल और सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे स्थायी हेलीपैड

प्रदेश में हवाई सुविधाओं का विस्तार होगा

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में विमानन सेवाओं और अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नागरिकों का विचार हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के साथ ही आपातकालीन सेवाओं, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने के लिए एयरपोर्ट, एयरस्ट्रिप और हेलीपैड के नेटवर्क का नागरिक विमानन नीति–2025 के अंतर्गत विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में एयरपोर्ट बढ़कर 8 हो गए हैं और शीघ्र ही इनकी संख्या 10 हो जाएगी। इसी तरह से प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्‍या भी निरंतर बढ़ रही है। पहले दुबई और अब अबूधाबी

के साथ इंदौर का हवाई संपर्क स्थापित हुआ है। सिंहरे?थ–2028 के लिये भी दताना–मताना एयरपोर्ट का विस्‍तार हो रहा है। नए एयरपोर्ट के विकास, सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थायी हेलीपैड का निर्माण और पीएमश्री एयर एम्बुलेंस एवं पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा से प्रदेश में हवाई सुविधाएं अधिक सुगम और व्यापक हो रही हैं।मध्यप्रदेश में वर्तमान में 8 एयरपोर्ट, 20 से अधिक एयरस्ट्रिप और 220 हेलीपैड हैं। वर्ष 2023–24 में प्रदेश में 5 प्रमुख एयरपोर्ट इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो संचालित थे। वर्ष 2024–25 में रीवा, दतिया और सतना को जोड़कर एयरपोर्ट की संख्या 8 हो गई है। उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट के विकास का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में हवाई सुविधाओं को और

दुर्गा पूजा से पहले फंड जारी करनेकीमांग

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले तुण्मूल कांग्रेस ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच का रुख किया। उन्होंने कोर्ट द्वारा नियुक्त उस स्पेशल ऑफिसर के खिलाफ यह कदम उठाया है, जो उन्हें पार्टी के तीन बेंचों के काराउंट्स को अपॉरेट करने की इजाजत नहीं दे रहा है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच के सामने दायर अपनी याचिका में ममता गुटा ने स्पेशल जज सुब्रत तालुकदार पर आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा से पहले पेसे निकालने की इजाजत नहीं दी। याचिका में कहा गया कि इस वजह से गुट त्योहार के मौसम से पहले घर का क्रियाया और ऑफिस के कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पा रहा है।

कर्नाटक के बल्लारी में मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप भाजपा नेता और चुनाव अधिकारियों पर प्राथमिकी

बेंगलुरु, एजेंसी। विशेष गहन पुनरीक्षण

(एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान बल्लारी सिटी विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट से 7,561 नाम हटाने की कोशिश करने के आरोप में भाजपा के बूथ लेवल एजेंट–1 (बीएलए–1), बल्लारी सिटी कॉर्पोरेशन के एक पार्षद और तीन अन्य लोगों के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज की गई। यह मामला वार्ड नंबर 23, बूथ नंबर 94 के कांग्रेस बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) गौतम की शिकायत पर दर्ज किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें बल्लारी सिटी कॉर्पोरेशन के पार्षद और भाजपा बीएलए–1 श्रीनिवास मोटकर, असिस्टेंट कमिश्नर नंदीश, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) सुमलता और केस वर्कर शरणबसवा शामिल हैं। शिकायत के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया 29 जून को शुरू हुई थी और 24 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी। इसके बाद वोटरों को नाम जुड़वाने के लिए दावे पेश करने और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था। शिकायत करने वाले का आरोप है कि 21 सितंबर को मोटकर ने बल्लारी

सिटी कॉर्पोरेशन इलाके में 7,561 वोटरों के नामों की दोबारा जांच की मांग वाली एक अर्जी स्वीकार की। शिकायत में कहा गया है कि चुनाव अधिकारियों ने पहले इस अर्जी को खारिज कर दिया था और इस बारे में एक पावती भी जारी की थी। इसके बावजूद आरोप है कि मोटकर ने 22 सितंबर को नाम हटाने के लिए ‘फॉर्म–7’ के तहत आवेदन जमा किए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित चुनाव अधिकारियों ने आपत्तियों के बावजूद वोटरों की दोबारा जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई और मोटकर के निर्देशों पर काम किया।

98.08 प्रतिशत वोटर अल्पसंख्यक समुदाय से थे

शिकायत में एक मुख्य आरोप यह है कि इन एप्लीकेशन में शामिल 7,561 वोटरों में से लगभग 98.08 प्रतिशत वोटर अल्पसंख्यक समुदाय से थे। शिकायत करने वाले का आरोप है कि ये एप्लीकेशन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के मकसद से जमा किए गए थे।

किसान हित में सहकारी ऋण व्यवस्था होगी सरल: डॉ. यादव

भोपाल/ खंडवा, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसान हित में सहकारी ऋण व्यवस्था को सरल और किसान हितैषी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को खंडवा जिले में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद थे और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीमच के चोंग कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने नीमच के किसानों से सीधे संवाद कर कृषि गतिविधियों, योजनाओं और उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच उन्नत खेती और कृषि व्यापार का प्रमुख केंद्र है। नीमच मंडी में कृषि उपज की आवक वर्ष 2023–24 की 53.46 लाख क्विंटल से बढ़कर 2025–26 में करीब 72 लाख क्विंटल हो गई। मंडी की आय भी बढ़कर करीब 34.5 करोड़ रुपए पहुंची। उन्होंने कहा कि जिले में 10 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक एवं जैविक खेती हो रही है। सिंचाई परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्यपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। गांधीसागर में चीता परियोजना से पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाएं बनने की बात भी कही।

वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग

के जरिए

नीमच के

किसानों से

संवाद

मोबाइल पर टोका तो भड़के तीमारदार, डॉक्टर-गार्ड से भिड़े; वार्ड में चले लात-घूसे

मरीजों के सामने जमकर

मारपीट, बीच-बचाव

करने आए लोग भी

घायल; वीडियो इंटरनेट

मीडिया पर वायरल

रीवा, एजेंसी। संजय गांधी

अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों के बीच उस समय दहशत फैल गई, जब मोबाइल पर बात करने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। मरीज के तीमारदार, डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड के बीच जमकर लात–घूसे चले। वार्ड में काफी देर तक हंगामा होता रहा। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, वार्ड में मरीज का तीमारदार मोबाइल पर बात कर रहा था। डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड ने उसे मोबाइल पर बात करने से रोकने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष एक–दूसरे से भिड़ गए। मारपीट के दौरान

संजय गांधी अस्पताल में

डॉक्टरों, सुरक्षा गार्डों और

मरीजों के तीमारदारों के बीच

विवाद की घटनाएं पहले भी

सामने आती रही हैं। ताजा

मारपीट ने अस्पताल प्रबंधन की

सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल

खड़े कर दिए हैं। अस्पताल जैसे

संवेदनशील परिसर में मरीजों

के सामने हिंसा होना व्यवस्था

की गंभीर स्थिति को उजागर

करता है।